सर्वेक्षण करने का काम हाथ में लिया गया है ।

(5) राउरकेला और दुर्गापुर में विशेष प्रकार के इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन कारखानों का अतिरिक्त पूंजीगत सुविधायें दी जा रही हैं ।

(6) मालिक-मजदूर सम्बन्धों में सुधार लाने के प्रश्न पर सम्बन्धित केन्द्रीय मजदूर संघों के साथ बातचीत की जा रही है ।

(7) खर्च को कम करने के लिए ओवर टाइम, विवरण-सूची के अनुसार संचालन, सामग्री के प्रयोग आदि पर नियन्त्रण को कड़ा कर दिया गया है ।

(8) उत्पादन की क्वालिटी की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिससे घटिया माल के उत्पादन के कारण होने वाली हानि को कम से कम किया जा सके ।

(9) आन्तरिक मांग को बढ़ाने के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है, उधार की सुविधायें दी जा रही हैं।

Public Sector Steel Plants

*3. SHRI E. K. NAYANAR:
SHRI MAYAVAN:
SHRI CHENGALRAYA NAIDU:
SHRI NAMBIAR:
SHRI UMANATH:
SHRI MOHAMMAD ISMAIL:
SHRI ANBUCHEZHIAN:
SSHRI DEIVEEKAN:
SHRI DHIRESWAR KALITA:
SHRI SATYA NARAIN SINGH:
SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI:
SHRI S. KUNDU:
SHRI MANIBHAI J. PATEL:

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal to set up a statutory organisation for Public Sector Steel Plants; and

(b) if so, the composition and functions of the proposed organisation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) and (b). The whole question of reorganisation of the Steel Industry in the Public Sector including the suggestion to set up a Statutory Corporation is still under the consideration of Government.

श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या यह सच है कि इन कारखानों में लो ग्रेड प्रोडक्शन की अधिकांश पैदावार होती है, और अगर ऐसा है तो क्या यह हकीकत नहीं कि इन कारखानों में ऐसे उच्च अधिकारी हैं जिन को न तो मार्केट ट्रेड का पता है और न इस चीज का पता है कि मार्केट में कौन सी चीज की खपत है । ऐसी परिस्थिति में जिन अधिकारियों के कारण प्रोडक्शन कम होता है उन को हटाने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है और क्या ऐसे आदमियों को हटा कर जिन लोगों को मार्केट का पूरा ज्ञान हो ऐसे आदमियों को वहां तायनात करना चाहती है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० बन्ना रेड्डी) : लो ग्रेड बेराइटी के प्रोडक्शन का फैक्टर इस कदर ज्यादा नहीं है कि सिर्फ उसकी वजह से सारे नुक सान आये हों । हालांकि मैं मानता हूं कि वह भी एक फैक्टर है । मार्केट कंडिशन्स की जांच पड़ताल करने के बाद प्राडक्शन करने का काम बराबर जारी है । उस में कुछ डिफेक्टस हैं, उसके लिहाज से जितनी चीजों में हम तब्दीली कर सकते हैं, वह की जा रही है । मगर इसके अलावा मशीनरी के इक्विपमेंट का भी एक पहलु रहता है और उसके अन्दर ही हम रद्दोबदल कर सकते हैं ।

श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या यह दुरुस्त है कि मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट रक्खा है उस में जो घाटा दिखाया गया है

इन कारखानों में उस से अधिक घाटा होता है और जो आंकड़े उन्होंने रक्खे हैं वह गलत हैं?

डा० चन्ना रेड्डी : मैं ने सही आंकड़े ही हाउस में रक्खे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : माननीय महोदय ने बतलाया कि करीब 22 करोड़ रु० का घाटा दिसम्बर तक हुआ है, और उन्होंने उसके कुछ कारण भी बतलाये हैं। मैं मंत्री महोदय से दो बातें पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि क्या यह बात सही है कि हमारे स्टील की प्रति टन कास्ट और स्टील के मुकाबले में ज्यादा आती है, जैसे कि टाटा के और और दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में, हालांकि वह वास्तव में कम आनी चाहिये। वह यह बतलायें कि हमारी कितनी कास्ट आती है और कितनी आनी चाहिये, और दूसरे कंट्रीज की कितनी आती है। दूसरी बात यह कि अभी तक जो हमारी फुल कपैसिटी है वह 26,15,250 टन है जब कि ऐक्चुअल प्रोडक्शन 17 लाख 80 हजार टन है, यानी करीब 8 लाख, 35 हजार, 226 टन हमारे प्लान्टस कम पैदा करते हैं, तो यह कपैसिटी वह कब तक प्रोडयूस करेंगे और उस से घाटा कितना कम हो जायेगा ?

डा० चन्ना रेड्डी : : हमारी स्टील फैक्ट्रीज के सामने जो कैपिटल कास्ट है वह 2500 रु० प्रति टन है और उस की वजह से हमारे कास्ट आफ प्रोडक्शन पर बड़ा असर पड़ता है। हम लोग इतने टन पर ही काम करने के लिये मजबूर हैं अपने स्टील प्लान्ट्स में और इस लिहाज से हम को ग्लोबल टेन्डर का फायदा उठाने का अवसर नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि दुनिया के जो और कारखाने हैं वह 70 प्रतिशत रेटेड प्रोडक्शन करने पर ईवन हो सकते हैं, यानी उन को कास्ट आफ प्रोडक्शन मिल जाता है। मगर यहां हम 90 से 94 प्रतिशत तक प्रोडक्शन करें तब ईवन हो सकते हैं। इसलिये कि हमारी कैपिटल कास्ट ज्यादा है। हमारा अनुमान है कि हम दो या ढाई साल के अन्दर 3–4 हजार तक ला सकेंगे। अभी तक डिबेलुएशन की वजह से भी यह हमारे लिये सम्भव नहीं हुआ। अभी हमारा रेट आफ प्रोडक्शन . . .

SHRI KANWAR LAL GUPTA: What is the cost of production in our steel plants and other steel plants in other countries? That is my question. Give me the statistics.

डा० चन्ना रेड्डी : हमारा ऐक्चुअल कास्ट आफ प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज जैसा नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप दुनिया का बतला दीजिये।

डा० चन्ना रेड्डी : हमारे यहां 2500 रु० पर टन कास्ट आफ प्रोडक्शन है। यह कैपिटलाइजेशन की वजह से अधिक है।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I want the actual cost of production in our steel plants. He is giving the reasons. I do not want that. I want the actual cost of production.

DR. CHANNA REDDY: I shall provide the figures later.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: The Minister should know the cost of production. It is strange that he does not know it.

डा० चन्ना रेड्डी : हमारे यहां अभी टोटल केपैसिटी के लिहाज से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इस की वजह यह है कि हमारे यहां पिछले दो सालों के अन्दर मांग बहुत कम हो गई है। मैं आप को बतला रहा हूं कि हमारे यहां आर्डर्स के कसेलेशन कितने हुए हैं। भिलाई में 95, 542 टन के आर्डर्स कसेल हुए, इसी तरह दुर्गापुर में 1,28,983 टन कैंसेल हुए और रूरकेला में 77,873 टन कैंसेल हुए।

SHRI RANGA: We make neither head not tail of it. What is the actual cost of production as it is found to be? It is a simple question. If he does not know it, let him say so.

DR. CHANNA REDDY: I said that I shall supply the figures later.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं ने दूसरा सवाल पूछा था कि हमारे यहां फुल कपैसिटी कब तक हो जायेगी और फुल कपैसिटी हो जाने के बाद हमारा घाटा कितना कम हो जायेगा।

डा० चन्ना रेड्डी : हमारी इंटर्नल डिमान्ड बढ़ने पर ही फुल कपैसिटी तक पहुंचने की गुंजाइश है। और जो भी हम अनुमान लगा सके हैं उस के मुताबिक दो या तीन साल तक हमारी इंटर्नल डिमान्ड बढ़ जायेगी। इस बीच हम खद एच एस एल और दूसरी जगह से 32 करोड़ करोड़ रु० तक का एक्सपोर्ट कर रहे हैं दो तीन साल में मुकाबले 21 करोड़ रु० के।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से बिक्री का 23 परसेन्ट सिर्फ डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में चला जाता है जब इस के मुकाबले टाटा आयरन ऐंड स्टील कम्पनी जो है उस के अन्दर केवल 9 परसेंट जाता है। हमारे और टाटा आयरन ऐंड स्टील कम्पनी के डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में प्रपोर्शन का इतना बड़ा फर्क क्यों है और कैसे इस को बराबर किया जा सकता है?

डा० चन्ना रेड्डी : हमारे पास कैपिटलाइजेशन कास्ट बहुत ज्यादा है और टाटा और इंडियन आयरन स्टील कम्पनी की फैक्ट्रीज 1920 और उस के पहले की हैं और उन की कैपिटल कास्ट कम होने की वजह से उन का डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट हमारे पब्लिक सेक्टर के स्टील प्लान्टस से बहुत कम है।

जैसा आनरेबल मैम्बर ने बताया है यह सही है कि हम को इसमें ज्यादा रकम देनी पड़ रही है।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : ओवर-कपिटलाइजेशन क्यों ज्यादा है? क्यों टाटा के इतना ज्यादा है?

डा० चन्ना रेड्डी : अभी रीसेन्टली किया है और उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। फिर केपिटलाइजेशन कास्ट, इन्टरेस्ट और डिप्रिसिएशन चालू किया जाता है।

SHRI N. K. SOMANI: Hindustan Steel is not an antiquated cottage industry but is one of the world's largest and the most modern amalgam of steel producing unit. If the demand has gone down as a result of Government's policies, may I know what special efforts are being made to export the products of Hindustan Steel and how do our prices compare with the prices in the international world markets?

DR. CHANNA REDDY: As I said, it is not really a cottage industry or an outdated thing, but the point is that it is in the initial stage with a large in-built capacity which has not yet been utilised, it becomes a little uneconomical. Regarding indigenous utilisation and the exports, I have already given the facts stating how we are making efforts. From Rs. 2 to 4 crores of exports during the last two or three years, the H.S.L. itself has registered exports of the order of Rs. 32 crores during this year. So, we are making efforts in this direction.

SHRI N. K. SOMANI: I also asked how our prices compare with the international prices....

MR. SPEAKER: He has already stated that he would give. Mr. Nayanar. Question 3 is also clubbed with this. He may ask his supplementary. The answer has already been read out.

SHRI E. K. NAYANAR: There are reports that the Hindustan Steel Plants

are now running at a loss of Rs. 88 crores comparing 1965-66 and 1966-67 production. There are reports that, even by exporting to South Vietnam, Bhilai is not fully utilising its capacity for production. In view of this and the other factors, may I know whether the Government are of the view that the present loss, mismanagement, anti-labour policy and corruption in the steel industry are due only to the absence of a statutory organisation and if so, what is the basis for drawing this conclusion? I also want to know whether the Government is bringing the private steel plants also under the State sector.

MR. SPEAKER: He has already answered.

DR. CHANNA REDDY: Regarding figures of losses, I have already given them. To say that all this is entirely due to absence of a statutory organisation may not be correct, though that fact is also under the consideration of the Government.

SHRI E. K. NAYANAR: About the loss, are the statistics correct?

MR. SPEAKER: He has said that he has already answered about the question of loss. About the other question regarding statutory organisation, the difficulties are not only because of that, but there are various other things also.

SHRI E. K. NAYANAR: Is the figure about loss correct or not?

DR. CHANNA REDDY: I have given just now. It is about 270 million.

MR. SPEAKER: Mr. Chengalraya Naidu.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: In view of the fact that the members do not know as to what is going on in the steel plants—from time to time there are directives from the Government and we do not know about them—Will the Government consider bringing out a consolidated Bill so that the House may pass the Bill and we may know what is happening in the steel plants and secondly, will the Minister consider setting up a statutory organisation at least for the steel plants in view of the heavy losses incurred by the steel plants?

DR. CHANNA REDDY: As I said, the matter of making it a statutory organisation is under consideration. It has certainly certain advantages and also the other side.

SHRI UMANATH: The hon. Minister has stated that they are considering the proposal to have a statutory organisation. I would like to know as to what is the state of affairs in the public sector undertakings so far as steel is concerned, what is the specific state of affairs that led to the Government considering this particular proposal. Secondly, while considering, what is the specific reason for the Government not including the private sector steel plants also to be brought under such a Corporation?

DR. CHANNA REDDY: The Administrative Reforms Commission has given its report on public sectar undertakings. On of its recommendations is on the lines suggested nemely that the public sector unit should generally be under a statutory organisation. In addition they have made the point that there will be opportunity for public debate on the details of the functioning of these units and also the actual demarcation of the zones or areas of functioning and the rights as between Government, Parliament and the public sector corporations. These are all the things which can be clearly defined once and for all when these things come before Parliament and we shall then have a clear idea about the whole thing, and later on, the usual freedom for a corporation to act successfully will be ensured. These are the considerations that are there before us.

SHRI UMANATH: Part (b) of my question has not been answered. I wanted to know why the question of including the private sector steel

plants was not being considered by Government.

DR. CHANNA REDDY: They are private units.

श्री मुहम्मद इस्माइल : सेक्रेटरी आर्गेनाइजेशन जो आप बनाना चाहते हैं यह कब तक बन जाएगी ? क्या इसकी कोई हद भी आपने मुकर्रर की है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसी तरह की और भी पब्लिक सैक्टर कम्पनियां हैं जहां इस तरह नुकसान हो रहा है उनके लिए भी क्या आप सोच रहे हैं कि इस तरह की आर्गेनाइजेशन होनी चाहिये ?

डा० चन्ना रेड्डी : यह चीज इस वक्त गवर्नमेंट के सामने है और बहुत जल्द इसके मुताल्लिक फैसला हो जायगा । जहां तक दूसरे पब्लिक सेक्टर यूनिटस का ताल्लुक है वह चीज भी गवर्नमेंट के सामने है लेकिन मैं उनके मुताल्लिक कोई ज्यादा तफसील तो नहीं दे सकता हूं ।

SHRI DHIRESWAR KALITA: The hon. Minister has stated that Government are considering the question of setting up a statutory organisation for the steel plants. May I know the broad features of the proposed statutory organisation and the lines on which it is going to be set up?

DR. CHANNA REDDY: We intend to bring forward before Parliament a Bill so that there could be an Act for the public sector units under the Hindustan Steel Corporation or the Hindustan Steel Ltd., and under the provisions of that Act the functioning will be regulated. That is the basis.

SHRI DHIRESWAR KALITA: I wanted to know the principles for the proposed composition of the statutory body.

DR. CHANNA REDDY: The basis or the principles will be just the same as we have at the moment under the H.S.L., but it will be regulated by the provision of the Act which would be passed by Parliament.

श्री सत्य नारायण सिंह : इस पार्लियामेंट ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बारे में एक कमेटी बनाई है, उनमें जो कमजोरियां हैं, जो भ्रष्टाचार है और जो हानि हो रही है उसे दूर करने के लिये कमेटी बनाई है और कमेटी ने कुछ सिफारिशें की हैं । लेकिन उन सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया है । ऐसी सूरत में अगर कमेटी की सिफारिशों पर अमल नहीं किया जाता है तो क्या कमेटी से कुछ सिद्ध होने की कोई सम्भावना है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कमेटी में मजदूरों के समर्थकों, कर्मचारियों के समर्थकों को भी लेने की कृपा की जाएगी ?

डा० चन्ना रेड्डी : मुझे नहीं मालूम कौन सी कमेटी की तरफ माननीय सदस्य ध्यान दिला रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार की ।

SHRI UMANATH: The recommendations of the Pande Committee are not being implemented.

SHRI S. KUNDU: The hon. Minister has stated that a large number of import orders had to be cancelled by the H.S.L. May I know whether it is due to lack of quality in production and also due to the fact that the items could not be supplied to them in time?

Recently, the Administrative Reforms Commission has given a report on the working of the public sector units, wherein they have stated that one of the reasons for the bad working of the public undertakings is the inbuilt security granted to the officials. Pending the passing of the Bill by Parliament, may I know whether the hon. Minister is going to do away with completely this in-built security and see that promotion takes pleac only on the basis of efficiency and merit?

Thirdly, in H.S.L. and other public sector undertakings, the Financial Advisers are appointed by the Managing Directors,

which is a very dangerous procedure. Is the Minister contemplating appointment of the Financial Advisers directly by the parliament or by the Government?

DR. CHANNA REDDY: Regarding orders that have been cancelled, it is not due to either of the reasons mentioned by the hon. Member, but it is because there has been recession and the original plan provisions of the Central and State Governments in regard to various projects have been cut down considerably. This has affected the total supplies that have to be cut down.

As regards the point that there is built-in security for the officers, this is not entirely correct. Action is taken wherever it has to be taken. In fact, the House is aware that three senior officers in Durgapur were dismissed because of the findings of the Pande Committee fixing responsibility on those officers.

On the question of the appointment of the Financial Adviser, that can be one view taken. He is not being appointed by the Managing Director of the company. In fact, there are certain people who believe, and strongly plead, that the appointment of the Financial Adviser should be left to the corporation itself so that his loyalty shall be to the corporation, instead of the present system of appointment by Government. That matter is also under consideration of Government.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: May I know how far the recommendations in regard to steel production made by the Mahtab Committee have been implemented by Government? As regards the setting up of a statutory organisation, has it anything to do with the previous decentralisation proposal made by Shri C. Subramaniam when he was Steel Minister?

DR. CHANNA REDDY: Most of the recommendations of the Mahtab Committee have been accepted and implemented. Regarding the statutory organisation, even the decentralisation proposal of 1963 referred to by the hon. Member when Shri C. Subramaniam was there, will not really have a direct bearing on it. But even in the case of the statutory corporation, that decentralisation can be done. I can inform the hon. Member that even that aspect is under consideration of Government.

श्री अब्दुल गनी डार: वजीर साहब ने फरमाया है कि इस साल 25 करोड़ रुपये का ज्यादा स्टील बाहर भेजा गया है। क्या वह यह बतायेंगे कि इस 32 करोड़ रुपये में उन्होंने जो फारेन एक्सचेंज कमाया है क्या वह परसेंटेज के लिहाज से 7 करोड़ रुपये के मुकाबले में ज्यादा है या कम ; अगर कम है, तो उस में सरकार को कितना नुक्सान उठाना पड़ा है ?

[شری عبدالغنی ڈار : وزیر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس سال ۲۵ کروڑ روپئے سے زیادہ اسٹیل باہر بھیجا گیا ہے - کیا وہ یہ بتائینگے کہ اس ۳۲ کروڑ روپئے میں انہوں نے جو فارین ایکسچینج کمایا ہے - کیا وہ پرسینٹیج کے لحاظ سے ۷ کروڑ روپئے کے مقابلے میں زیادہ ہے یا کم ہے - تو اس میں سرکار کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے ؟]

डा० चन्ना रेड्डी : फ़ारेन एक्सचेंज हासिल करने के लिये हमारी तरफ़ से जो कीमत दी जा रही है, वह इन्टरनेशनल मार्केट में काम्पीटीटिव है और इस वजह हमें अपने कास्ट आफ प्राडक्शन में एक्चुअली नुक्सान उठाना पड़ा है। उसके आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं, लेकिन निस्बतन उसी प्रोपोर्शन में हमें नुकसान उठाना पड़ा है।

श्री अब्दुल गनी डार : क्या वे आंकड़े इस हाउस को दिये जायेंगे, ताकि यह मालूम हो सके कि सरकार की तरफ़ से यह दिखावा किया जाता है कि हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें देश का नुकसान होता है ?

[شری عبدالغنی ڈار - کیا وہ آنکڑے اس هاؤس کو دئے جائینگے - تاکہ یہ معلوم هو سکے کہ سرکار کی طرف سے یہ دکھاوا کیا جاتا هے کہ هم اتنا ایکسپورٹ کر رهے هیں - لیکن اس میں دیش کا نقصان هوتا هے -]

डा० चन्ना रेड्डी : एक्सपोर्ट का काम दिखाने से ताल्लुक नहीं रखता है। फ़ेक्चुअल पोजीशन यह है कि एक्सपोर्ट करने से हमें फ़ारेन एक्सचेंज मिलता है । यह ठीक है कि फ़ारेन एक्सचेंज कमाते वक्त इन्टर-नेशनल मार्केट में काम्पीटीटिव प्राइसिज देने की वजह से कास्ट ग्राफ़ प्राडक्शन में नुक्सान उठाना पड़ता है। उसके ग्रांकड़े मैं जल्दी ग्रानरेबल मेम्बर को भेज दूंगा।

श्री मधु लिमये : पिछले बजट सत्र में मैंने पांडे कमीशन की सिफारिशों पर बहस उठाई थी। उस वक्त मैंने मांग की थी कि उन सिफारिशों पर कैसे ग्रमल किया जा रहा है, मंत्री महोदय उसके बारे में समय समय पर रपट दें। उन्होंने ग्राश्वासन भी दिया था कि वह समय समय पर रपट देंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय की ग्रोर से इस सप्ताह के दौरान इस सम्बन्ध में कोई रपट सदन के सामने ग्रायेगी । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान स्टील के चेयरमैन के तौर पर किसी पराजित मंत्री को नियुक्त करने का उनका विचार है । उनको देखना चाहिये कि उत्पादन पर इसका क्या ग्रसर होगा । जो पराजित मंत्री हैं, वह उत्पादन नहीं बढ़ा सकेगा । मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि हैवी इंजीनियरिंग का चेयरमैन भी एक पराजित मंत्री को बना दिया गया है ।

डा० चन्ना रेड्डी : हम पांडे कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में पीरियाडिकल रिपोर्टस मंगा कर उनको जांचने का काम कर रहे हैं जैसा कि ग्रानरेबल मेम्बर चाहते हैं, मैं एक हफ्ते में तो नहीं, लेकिन जल्द से जल्द लेटैस्ट पोजीशन हाउस के सामने रखूंगा जहां तक चेयरमैन का ताल्लुक है, इस किस्म की कोई बात हमारे सामने नहीं ग्राई है ।

श्री मधु लिमये : : प्राणप्रसाद को भी नियुक्त न कीजिये, क्योंकि बर्ड एन्ड कम्पनी का मामला है ।

SHRI BEDABRATA BARUA: One factor that has not found a place in the reply of the hon. Minister is the cut-back in the orders for wagons by the railways. When there is a recession, it is the public exchequer that comes forward to aid. So, may I know what steps they are taking to persuade the railways to help the industry in this regard?

DR. CHANNA REDDY: The hon. member is aware, even the railways had to cut down considerably their plan programmes, and quite a large number of orders had to be cancelled.

SHRI LOBO PRABHU: In view of the admission of the Minister that the public sector plants are over-capitalised, that they cannot sell at competitive prices internationally, that there is idle capacity etc., may I ask him a simple question? Why are you going to add more to our steel production? Why do you want Bokaro? Are not four white elephants enough?

MR. SPEAKER: That is a matter of policy.

श्री शिव चन्द्र झा : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार जो पब्लिक सेक्टर के इस्पात कारखानों के लिये एक स्टैचुटरी ग्रार्गनाइ-जेशन बनाने की बात सोच रही है, क्या उसके ग्रन्तर्गत वर्कर्ज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेन्ट के लिए भी कोई योजना बन रही है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं, यदि हां, तो उसका रूप क्या होगा ?

डा० चन्ना रेड्डी : इस का ताल्लुक तफ़सीलात से है। इसलिए मैं ग्रभी इस बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं ।

SHRI D. C. SHARMA: I have read the statement, and from the statement I find that there is hardly any ill from which public undertakings can suffer which is not there so far as the steel plants are concerned. Internally, the demand is slack. The Pande Committee Report with regard to coke-oven and furnace is yet to be implemented. The production of special steel is yet in the air. Diversification of production is wishful thinking. Additional capital facilities are yet to be found. Labour-management relations require improvement. Expenses are mounting and control is not effective. The quality of steel produced is not as high as it should be. So, may I know from the hon. Minister how all these organic ills from which these steel plants are suffering will be cured by bringing into being a public steel corporation which he is thinking of?

DR. CHANNA REDDY: All these ills which the hon. Member referred to are being attended to and we have been able to cure a number of them.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER: We have taken about forty minutes over this question. I do not know whether we should pursue this any further. When I allow more time, even people who did not stand up originally stand up. What am I to do? Next question.

Loss to Railways during Language Agitation

†

*4. SHRI CHENGALRAYA NAIDU:
SHRI R. R. SINGH DEO:
SHRI D. N. DEB:
SHRI Y. A. PRASAD:
SHRI BEDABRATA BARUA:
SHRI HEM BARUA:
SHRI SRADHAKAR SUPAKAR:
SHRIMATI SUSHILA ROHATGI:
SHRI J. MOHAMED IMAM:
SHRI KANWAR LAL GUPTA:
SHRI RAM GOPAL SHALWALE:
SHRI N. S. SHARMA:
SHRI PRAKASH VIR SHASTRI:
SHRI SHIV KUMAR SHASTRI:
SHRI RAM SEWAK YADAV:
SHRI MOHSIN:
SHRI G. C. DIXIT:
SHRI VISHWA NATH PANDEY:
SHRI JUGAL MONDAL:
SHRI HUKAM CHAND KACHWAI:
SHRIMATI TARKESHWARI SINHA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total loss suffered by the Railways during the recent language agitation in the country, State-wise; and

(b) the approximate cost of replacement for damaged property?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI PARIMAL GHOSH): (a) and (b). A statement giving the required information is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a)

Name of the State	*Amount of loss*
	Rs.
Andhra Pradesh	1,00,068.00
Bihar	23.00
Delhi	20.00
Kerala	15,693.00
Madhya Pradesh	1,400.00
Mysore	3,000,00
Madras	19,63,626.00
Uttar Pradesh	4.14,231.00
Total	24,98,061.00

(b) *Cost of replacement of damaged property.* The replacement cost would approximate to the value of loss given in (a).